सी.बी.आई., ए.एच.डी., पटना ए

वी

ब्रज भूषण प्रसाद और अन्य।

5 अक्टूबर 2001

[के.टी. थॉमस, सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी और बी यू.सी. बनर्जी, जे.जे.]

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000-धारा 89-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-धारा 4(2), 13(एल)(सी) एवं 13(एल)(डी)-मामला;; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत-मुकदमा-प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पूर्ववर्ती बिहार राज्य में दायर मामलों का निर्धारण-झारखंड राज्य के क्षेत्रों में उत्पन्न मामलों में कार्रवाई का कारण-बी (राज्य के मामले में विभाजन-मामलों के हस्तांतरण के लिए दावा) झारखंड राज्य की न्यायालयों में, अधिकार क्षेत्र का स्थान उस स्थान के संदर्भ में निरूपित किया जाएगा जहां मुख्य अपराध किया गया था और न कि जहां संबद्ध कृत्य किए गए थे-यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई के लिए जगह निर्धारित करता है, सी.आर.पी. का प्रावधान। उस सीमा तक विस्थापित हो जाएगा-इसलिए, मामलों को झारखंड राज्य के न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 4(2), 179, 180।

दंड संहिता प्रक्रिया, 1973/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-

धारा 181(4)14(2)-के बीच भेद-विवेचना।

कानून की व्याख्या कानून-व्याख्या को कानून के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए
कानून व्यावहारिकता के साथ बनाया जाना चाहिए, न कि पांडित्यपूर्ण तरीके से या संकीर्ण तरीके से।

सिद्धांत

नोसितुर ए सोशिएस --व्याख्या का सिद्धांत।

शब्दों और वाक्यांशों :

"विशेष रूप से"-अर्थ -बिहार की धारा 89 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के संदर्भ में।

चारा घोटाले से जुड़े 64 मामले दर्ज किये गये, जिसमें जाँच सी.बी.आई. द्वारा आयोजित किया जाना था। उनमें से 36 मामलों में सी.बी.आई. द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत पटना में विशेष न्यायालय बनाई गई।

बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य का विभाजन, बिहार एवं झारखण्ड में होने के उपरान्त दिनांक 15/11/2000 जिस दिन विभाजन के पश्चात नये राज्य

का जन्म हुआ) को सी०बी०आई० ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस आशय का वाद दायर किया कि उन 36 मामलों को जिसमें आपराधिक कृत्य झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत किया गया था, को झारखण्ड राज्य स्थानांतरित किया जाय।

उच्च न्यायालय ने माना कि चूँकि " धारा 179 और 180 सीआर.पी.सी. के अनुसार,"पटना में किए गए कुछ संबद्ध अधिनियमों के आधार पर" पटना में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से बाहर नहीं रखा गया था, कार्यवाही को विशेष रूप से झारखंड राज्य से संबंधित नहीं माना जा सकता था और इसलिए, मामले वर्तमान बिहार राज्य में ही बने रह सकते हैं।

इस न्यायालय में अपील में सी.बी.आई. तर्क दिया कि का अधिकार क्षेत्र मामले विशेष रूप से झारखंड राज्य के न्यायालयों में थे और प्रश्न यह है कि क्या पटना की न्यायालयों के लिए भी अधिकार क्षेत्र का निर्धारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 4(2) के संदर्भ में किया जाना था, न कि सीआरपीसी के किसी प्रावधान के मद्देनजर। पी.सी.; और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 में 'विशेष रूप से' शब्द का अर्थ "काफी हद तक या बड़े हिस्से के लिए या मुख्य रूप से" के रूप में समझा जाना चाहिए।

उत्तरदाताओं-अभियुक्तों ने तर्क दिया कि चूँकि अपराध पटना में स्थित अधिकारियों द्वारा किए गए थे, इसलिए पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 में विशिष्टता का परीक्षण मामलों की सुनवाई के लिए पटना में न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से मुक्त नहीं कर सकता है; और यह कि पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 में 'विशेष रूप से' शब्द का "अन्य सभी को छोड़कर" के अलावा कोई अर्थ नहीं हो सकता है।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए

माना गया: 1. अपील में शामिल सभी 36 मामले स्थानांतरित कर दिए गए धारा 89 के प्रवर्तन द्वारा नियत दिन (अर्थात् 15.11.2000) को झारखंड जी राज्य के क्षेत्रों के भीतर स्थित संबंधित न्यायालयों को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 का। [645-ई]

2. क्षेत्राधिकार का स्थान संदर्भ द्वारा निर्धारक होगा वह स्थान जहाँ मुख्य अपराध किया गया था। तथ्य यह है कि अन्य संबद्ध कृत्य अलग-अलग स्थानों पर किए गए, मुकदमे के स्थान को ऐसे अन्य स्थानों में बदलने के लिए शायद ही पर्याप्त होंगे। यह निश्चित है कि जब वास्तव में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत अपराध किया गया था, यह अन्य क्षेत्रों पर विचार करने के लिए एक अनावश्यक अभ्यास है जिसमें कुछ संबद्ध गतिविधियां, जैसे साजिश या तैयारी, या यहां तक कि प्रारंभिक या आकस्मिक कार्य भी किए गए, जिनमें परिणामी परिणाम

भी शामिल हैं। [644-ई; 641-एच; 642-ए]

धनेश्वर नारायण सक्सैना बनाम. दिल्ली प्रशासन [1962] 3 एससीआर 259; एम. नारायणन नांबियार बनाम. केरल राज्य, [1963] पूरक। 2 एससीआर 724; गुजरात राज्य बनाम. मानशंकर प्रभाशंकर द्विवेदी, [1972] 2 एससीसी 392; मेजर एस.के. काले वि. महाराष्ट्र राज्य, [1977] 2 एससीसी 394; भारत संघ बनाम मेजर. आइ.सी. लाला आदि। [1973] 2 एससीसी 72 और के. भास्करन बनाम सी शंकरन वैद्यन बालन और अन्य, [1999] 7 एससीसी 510, प्रतिष्ठित।

बनवारीलाल झुनझुनवाला और अन्य . व्. यूनियन ऑफ़ इंडिया, एयर (1959) केरल 311, स्वीकृत।

पुरुषोत्तमदास डालमिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1962] 2 एससीआर 101; एल.एन. मुखर्जी बनाम. मदास राज्य [1962] 2 एससीआर 116 और बनवारी लाल डी झुनझुनवाला और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1963] अनुपूरक। 2 एससीआर 338, संदर्भित।

3. पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 के मुख्य उद्देश्य के अनुसार, आपराधिक मामलों का स्थानांतरण इस धारा के अंतर्गत आने वाला एकमात्र विषय नहीं है। यह प्रावधान विभाजन के बाद सभी कार्यवाहियों से संबंधित फाइलों या अभिलेखों को आवंटित करने का प्रयास करता है, यदि उन्हें निर्धारित दिन के बाद स्थापित किया जाना था। कोई भी व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके, न कि वह जो संबंधित राज्यों के अधिकारियों के लिए भ्रम या परेशानी या यहां तक कि विस्मय पैदा कर सकती है। दूसरे शब्दों में, व्याख्या व्यावहारिकता के साथ की जानी चाहिए, न कि पांडित्यपूर्ण या संकीर्ण तरीके से। आपराधिक मामलों के उद्देश्यके लिए स्थानांतरित किए जाने वाले मामले की विषय-वस्तु को ध्यान में रखना होगा। इस पर विचार करते समय, यह ध्यान में रखना होगा कि सभी 36 मामले मुख्य रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए हैं और इसलिए वे सभी विशेष न्यायाधीशों की न्यायालयों के समक्ष विचारणीय हैं। इसलिए, वर्तमान प्रश्न को संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान। [639-डी; इ]

4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(सी) या धारा 13(1)(डी) के तहत होता है तो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में एकमात्र निर्धारक कारक वह स्थान होता है जहां अपराध किया गया।

अनुभाग के साथ पंक्तिबद्ध एक गैर-अस्पष्ट खंड का अभाव भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(2) से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उपधारा सीआरपीसी के प्रावधानों के अधीन है। पी.सी. सीआरपीसी की धारा 4(2) का वाचन। (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नहीं) यह निश्चित संकेत देता है कि कानूनी स्थिति इसके विपरीत है। धारा 4 सीआर.पी.सी. भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों

के तहत अपराधों के मुकदमे के संबंध में है। उपधारा

(1) इसका संबंध केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों से है। उपधारा बी

(2) "किसी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों" से संबंधित है। इस प्रकार, यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने उस अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई के लिए कोई स्थान निर्धारित किया है तो सीआर.पी.सी. का प्रावधान उस पर लागू होता है। परीक्षण के स्थान के संबंध में उस सीमा तक विस्थापित किया जाएगा। [643-ए; बी.]

5. जब आरोप में अपराध या दंडनीय अपराध शामिल हो तब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ-साथ ऐसे किसी अपराध को करने की साजिश या प्रयास करने या किसी भी तरह के अपराध के लिए उकसाने के अपराध के तहत, उस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मुख्य अपराध अकेले किया गया था। संहिता की धारा 181(4) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(2) के बीच अंतर है। पूर्व प्रावधान में जब कम से कम चार न्यायालयों की परिकल्पना की गई है जिनके पास गबन से जुड़े मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बाद के प्रावधान ने इसे एक न्यायालय तक सीमित कर दिया है यानी उस क्षेत्र के लिए विशेष न्यायाधीश की न्यायालय "जिसके भीतर अपराध किया गया था। किसी अन्य न्यायालय के लिए " उस अपराध के मुकदमे की परिकल्पना की गई। [642-ई;एफ]

6. इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि कार्यवाही कहाँ से संबंधित है इन अपीलों में शामिल 36 मामले निर्धारित किए गए होते, यदि उन्हें नियत दिन के बाद स्थापित किया जाता, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि "विशेष रूप से" शब्द का अर्थ "पर्याप्त रूप से सभी या बड़े हिस्से के लिए या मुख्य रूप से" समझा जाना चाहिए। नोस्किटुर ए सोशियस का सिद्धांत (एक शब्द का अर्थ इसके साथ आने वाले या संबद्ध शब्दों से जाना जाना चाहिए) वैधानिक प्रावधान में शब्दों के आयात को समझने में बहुत प्रासंगिक है। इसलिए, "विशेष रूप से क्षेत्र से संबंधित कार्यवाही" शब्दों के निहितार्थ को आसपास के संदर्भ से आंका जाना चाहिए। पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 कहती है कि "किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय के अलावा) न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी" के समक्ष नियत दिन से पहले की कार्यवाही लंबित है, झारखंड राज्य के "संबंधित न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी" को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। [639-सी; 638-एफ-एच; 639-ए]

बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्प[1978] 2 एससीसी2131; रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम सीसीई, [1990] 3 एससीसी 447; ओसवालएगो मिल्स लिमिटेड बनाम सीसीई, [1993] सप्लिमेंट। 3 एससीसी 716; के. भागीरथी जी. शेनॉय एवं अन्य बनाम के.पी. बल्लाकुराय एवं अन्य [1999] 4 एससीसी 135 और लोकमत न्यूजपेपर्स (पी) लिमिटेड बनाम शंका1प्रसाद, [1999] 6 एससीसी 275, संदर्भित।

साल्वेशन आर्मी बनाम होहेन (मो., 354, मो.107, 188 एसडब्लू 2रे 826; अनोका काउंटी बनाम

सिटी ऑफ सेंट पॉल, (1999) अमेरिकन लॉ रिपोर्ट्स 1137; अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन बनाम एसेसर्स ऑफ टाउन ऑफ 406 एनवाईएस 583 और क्लैमथ सिंचाई जिला. बनाम रोजगार प्रभाग, (534) पी. 2डी 1990, संदर्भित।

ब्लैक लॉ.डिक्शनरी, कोरपस ज्यूरिस सेकुंडम खंड 33 का पृष्ठ 113, संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1009- 1010 ऑफ 2001

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 4.5.2001 के निर्णय और आदेश से। 2001 का आर. नं. 1 और 2.

साथ

सी.आर.एल. ए. की संख्या 1013-1014 सन2001 ।

हरीश एन. साल्वे, सॉलिसिटर जनरल, कपिल सिब्बल, पी.एस. मिश्रा, अनूप चौधरी, सुशील कुमार, ए.डी.एन. राव, पी. परमेश्वरन, आर.पी. सिंह, सी.आर.सिन्हा, बी.बी. सिंह, इरशाद अहमद, अजीत कुमार सिन्हा, श्रीमती सरला चंद्रा (एनपी), आर.के. खन्ना, टी. .हर्षवर्धन, विष्णु शर्मा, उपेन्द्र मिश्रा, राजेश प्रसाद सिंह, सुश्री रितु जलाली, मनु शंकर मिश्रा, चन्द्र शेखर, हिमांशु शेखर, गौरव अग्रवाल, जोसेफ पॉक्कट, प्रशांत कुमार, सुश्री निरंजना सिंह, आलोक कुमार, तपेश कुमार सिंह, आर.पी. वाधवानी, शिशिर पिनाकी, आर.पी. वाधवानी, अमित कुमार, के.एल. तनेजा, रविशंकर द्विवेदी, रुद्रेश्वर सिंह, संजय जैन, सुश्री कामिनी जयसवाल, सुश्री शोमिला बखशी और सुश्री ऐश्वर्या राव उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

थॉमस, जे. अनुमोदन स्वीकृत.

सवाल छोटा है लेकिन विचार का दायरा काफी बढ़ गया. प्रश्न का उत्तर कुछ अभियुक्तों के लिए फायदेमंद और कुछ अन्य अभियुक्तों के लिए नुकसानदेह हो सकता है जो बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों में शामिल हैं। जिन्हें बड़े करीने से "बिहार चारा घोटाला मामले" उपनाम से स्टाइल किया गया है।

ये मामले सुनियोजित धोखाधड़ी के कृत्यों की एक श्रृंखला से संबंधित थे, जिनके द्वारा राज्य के प्रशासन में कई उच्च अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी या मिलीभगत से उक्त उद्देश्य के लिए फर्जी बिल और अन्य झूठे दस्तावेज तैयार करने के बाद सार्वजनिक धन की भारी मात्रा में लूट या गबन की गई थी। हालाँकि अब प्रत्येक मामले में लूटी गई भारी रकम का उल्लेख करना अनावश्यक है, हमें

बताया गया है कि उनकी कुल राशि 720 करोड़ रुपये से अधिक है। इस मामले में जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों (लालू प्रसाद यादव और डॉ. जे. अग्निनाथ मिश्र) के अलावा उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति शामिल हैं।

उपरोक्त इंगित प्रश्न 15 नवंबर, 2000 की आधी रात को सामने आया, जब तत्कालीन बिहार राज्य ने खुद को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (संक्षेप में 'अधिनियम') नामक संसद के अधिनियम द्वारा दो राज्यों में विभाजित कर दिया। इसका एक क्षेत्र झारखण्ड नामक एक नया राज्य बन गया जबकि शेष क्षेत्र वर्तमान बिहार राज्य बन गया।

हमें बताया गया है कि चारा घोटाले को लेकर 64 मामले दर्ज किये गये हैं. पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा करने का निर्देश दिया गया था, जिसे इस न्यायालय ने बिहार राज्य और राज्य सरकार के फैसले के अनुसार कुछ संशोधनों के साथ पुष्टि की थी। बिहार राज्य एवं अन्य बनाम रांची जिला समता पार्टी एवं अन्य [1996] 3 एस.सी.सी. 682। यह विवादित नहीं है कि उपरोक्त में से 52 मामलों में झारखण्ड स्थित सरकारी खजाने से भारी मात्रा में धन की निकासी शामिल है। वे क्षेत्र जो अब झारखण्ड राज्य के अंतर्गत आते हैं। उन 52 मामलों में से, 36 मामलों में सीबीआई द्वारा नियत दिन यानी 15.11.2000 से पहले पटना स्थित विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है। ये अपीलें उन 36 मामलों से संबंधित हैं।

15.11.2000 की मध्य रात्रि के बाद झारखण्ड राज्य में सीबीआई की ओर से कहा गया कि उन 36 मामलों को स्थानांतरित कर दिया गया है। सीबीआई के उस दावे का उन मामलों के कुछ आरोपियों (लालू प्रसाद यादव और डॉ.जगन्नाथ मिश्रा सहित) ने विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि उनमें से कोई भी मामला स्थानांतरित नहीं किया गया है। इस प्रकार सरल प्रश्न यह है कि क्या उन सभी या उनमें से किसी भी मामले को झारखंड राज्य में स्थित न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था जब मध्य रात्रि को नए राज्य का जन्म हुआ।

पटना उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया। आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने यह विचार किया कि 36 मामलों में से कोई भी झारखंड राज्य में स्थानांतरित नहीं किया गया है, हालांकि पूर्ण पीठ के विद्वान न्यायाधीशों में से एक ने कहा कि 23 मामले (उक्त 36 मामलों में से) झारखंड को चले जाने चाहिए थे।

इस प्रकार उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के अनुसार 36 मामलों के संबंध में सीबीआई के दावे को खारिज कर दिया।

दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पूर्ववर्ती बिहार राज्य के विभाजन की अगली कड़ी के रूप में मामलों का स्थानांतरण अधिनियम में शामिल वैधानिक प्रावधान के संचालन का परिणाम है। उक्त अधिनियम की धारा 89 इस प्रकार है:

"89(1) किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय के अलावा) के समक्ष नियत दिन से ठीक पहले लंबित प्रत्येक कार्यवाही। किसी भी क्षेत्र में न्यायाधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी, जो उस दिन बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, यदि यह संबंधित कार्यवाही है विशेष रूप से क्षेत्र, जो उस दिन से झारखंड राज्य का क्षेत्र है, उस राज्य के संबंधित न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी को हस्तांतरित हो जाएगा।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई कार्यवाही होनी चाहिए उप-धारा (1) के तहत स्थानांतरित होने पर, इसे पटना उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा और उस उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

(3) इस खण्ड में-

(क) 'कार्यवाही' में कोई मुकदमा, मामला या अपील शामिल है; और

(ख) राज्य में 'संबंधित न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी' झारखण्ड का अर्थ है-

(i) वह न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी जिसमें या जिसके समक्ष कार्यवाही रखी जाती यदि वह नियत दिन के बाद शुरू की गई होती; या

(ii) संदेह की स्थिति में, उस राज्य में ऐसे न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी, जो नियत दिन के बाद, जैसा भी मामला हो, उस राज्य की सरकार या केंद्र सरकार द्वारा या नियत दिन से पहले निर्धारित किया जा सकता है। मौजूदा बिहार राज्य की सरकार द्वारा संबंधित न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी होगा।"

नियत दिन (यानी 15.11.2000) से पहले पूर्ववर्ती बिहार राज्य में वे सभी क्षेत्र शामिल थे जो अब झारखंड राज्य में शामिल हैं और साथ ही वे क्षेत्र भी जो वर्तमान बिहार राज्य में शामिल हैं। झारखण्ड राज्य मुख्यतः तीन क्षेत्रों से मिलकर बना है- (1) उत्तरी छोटानागपुर (2) दक्षिणी छोटानागपुर (3) संधाल परगना।

धनबाद, रांची और चाईबासा में स्थित सरकारी खजाने सभी झारखंड क्षेत्र के भीतर स्थित थे। पटना शहर, जो अविभाजित राज्य बिहार की राजधानी थी, वर्तमान बिहार राज्य के क्षेत्र में आता है। पटना अब वर्तमान बिहार राज्य की राजधानी है। उपरोक्त जानकारी प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए उपयोगी है:

दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि सभी 36 मामलों (यहां शामिल) में आरोप झारखंड क्षेत्र के क्षेत्रों में स्थित कोषागारों से करोड़ों रुपये की निकासी से संबंधित थे। बिहार राज्य के विभाजन से बहुत पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में पीसी अधिनियम) के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए न्यायालयें स्थापित की गई थीं। अधिसूचना के अनुसार बिहार सरकार द्वारा 19.4.1994 को जारी, विशेष न्यायाधीशों की तीन न्यायालयें बनाई गईं; एक धनबाद में, दूसरा रांची में और तीसरा पटना में। धनबाद में बनाए गए न्यायालय को "उत्तरी छोटानागपुर के विभाजन के तहत सभी क्षेत्रों" पर अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था। रांची में बनाई गई न्यायालय को "दक्षिण छोटानागपुर के विभाजन के तहत सभी क्षेत्रों" पर अधिकार क्षेत्र दिया गया था। पटना में बनाए गए न्यायालय को शेष क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र दिया गया था।

22.5.1996 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा पटना में विशेष न्यायाधीश की एक और न्यायालय स्थापित की गई, जिसके अनुसार छोटानागपुर के उत्तर और दक्षिण को छोड़कर सभी पटना क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र दिया गया था। इसका मतलब है, वहाँ पटना में दो न्यायालयें थीं जिनका क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार एक ही क्षेत्र पर था। फिर भी 5.6.96 को जारी अधिसूचना द्वारा पटना में ही विशेष न्यायाधीश की एक और न्यायालय स्थापित की गई। इस न्यायालय को "बिहार राज्य के संपूर्ण क्षेत्र" पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था।

अधिसूचना दिनांक 5.6.1996 द्वारा विशेष न्यायाधीश का न्यायालय बनाया जा सकता है इस प्रकार पूरे अविभाजित बिहार राज्य पर ऐसे समय में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है जब पहले बनाई गई एक न्यायालय (19.4.1994 की अधिसूचना के अनुसार) झारखंड क्षेत्र के भीतर आने वाले दो क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, अंतिम निर्मित न्यायालय को अन्य सभी न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार की तुलना में समवर्ती क्षेत्राधिकार के साथ निवेश किया गया था। यह अंतिम अधिसूचना संभवतः जांच एजेंसियों के लिए यह तय करने में समस्याएँ पैदा हो गई होंगी कि किस न्यायालय को चुना जाए। पीसी अधिनियम की धारा 4(2) के तहत आरोप पत्र दाखिल करने के लिए, (जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं, वहां अपराधों की सुनवाई केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश द्वारा की जाएगी)। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई।

उपरोक्त स्थिति में ही उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को 13.6.1996 को एक पत्र लिखकर उन्हें निर्देश दिया गया कि वे पशुपालन घोटाले (चारा घोटाले) से संबंधित सभी मामलों को बिना क्षेत्र प्रतिबंधित के निपटाने के लिए 5.6.1996 की अधिसूचना के अनुसार नियुक्त विशेष न्यायाधीश को सूचित करें। क्षेत्र के प्रतिबंध"। आक्षेपित निर्णय में उक्त पत्र की कानूनी वैधता पर हाई कोर्ट की फुल बेंच ने रजिस्ट्रार पर संदेह जताया था। हमारे सामने भी उस पत्र की इस आधार पर आलोचना की गई थी कि केवल केंद्र सरकार के पास यह निर्दिष्ट

करने की शक्ति है कि दोनों न्यायालयों में से कौन सी न्यायालयें किसी विशेष वर्ग के मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। ऐसा प्रावधान पीसी अधिनियम की धारा 4(2) में है।

जैसा भी हो, हम उक्त पत्र की वैधता या अन्यथा से संबंधित वर्तमान विवाद का निर्णय करेंगे।

हमारे समक्ष यह विवादित नहीं है कि झारखंड क्षेत्र के भीतर स्थित विशेष न्यायाधीशों की न्यायालयों के पास अब शामिल सभी 36 मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है। उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय के अनुसार, इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र भी पटना की न्यायालय को है। ऐसे मामलों में विभिन्न अभियुक्तों के खिलाफ कथित विभिन्न कृत्यों पर प्रकाश डाला गया और यह पाया गया कि पटना की विशेष न्यायालय को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में संहिता) की धारा 179 और धारा 180 के तहत अपराध की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था। . पूर्व धारा यह सक्षम करती है कि शामिल अपराध की जांच या उस न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसा अपराध किया गया था या परिणाम सामने आया था। अगामी धारा के तहत अपराधों की जांच या सुनवाई उस न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर या तो मुख्य कार्य किया गया था या मुख्य कार्य से संबंधित अन्य कार्य किए गए थे। उन प्रावधानों से संकेत लेते हुए उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने पाया कि चूंकि पटना में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से बाहर नहीं रखा गया था (पटना में किए गए कुछ संबद्ध कृत्यों के आधार पर) उन कार्यवाहियों को विशेष रूप से झारखंड राज्य से संबंधित नहीं माना जा सकता है, और इसलिए मामले वर्तमान बिहार राज्य में ही रह सकते हैं।

भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री हरीश एन. साल्वे, जिन्होंने सीबीआई के लिए तर्क दिया, ने कहा कि आक्षेपित फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया संपूर्ण दृष्टिकोण भ्रामक है क्योंकि सवाल यह है कि क्या धारा 179 के दृष्टिकोण से पटना की न्यायालयों का भी क्षेत्राधिकार था, या संहिता की धारा 180, अधिनियम की धारा 89 के दायरे से बाहर है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि प्रश्न का निर्धारण पीसी अधिनियम की धारा 4(2) के संदर्भ में किया जाना चाहिए, न कि सीआरपीसी के किसी प्रावधान के आधार पर। उनके अनुसार, परीक्षण यह है: यदि वही विज्ञापन नियत दिन के बाद किए गए थे और मामले शुरू किए जाने थे, तो क्या उन्हें झारखंड राज्य के भीतर स्थित न्यायालयों में दायर किया गया होगा। श्री हरीश एन. साल्वे के अनुसार यदि उपरोक्त परीक्षण का परिणाम सकारात्मक है, तो अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वर्तमान मामलों को नियत दिन पर झारखंड राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

विद्वान वरिष्ठ वकील (आपराधिक मामलों में आरोपी प्रतिवादियों में से एक की ओर से उपस्थित) श्री अनूप चौधरी ने सॉलिसिटर जनरल की दलीलों का समर्थन करते हुए आगे कहा कि अधिनियम की धारा 89 में 'कार्रवाई के कारण' की कानूनी अवधारणा की परिकल्पना नहीं की गई

थी और इस प्रकार उच्च न्यायालय ने यह तय करने के उद्देश्य से कि उस स्थान पर भी कार्रवाई का कारण उत्पन्न हो सकता था, पटना में किए गए कुछ कृत्यों को स्वीकार करते हुए गलती कर दी। श्री सुशील एक अन्य प्रतिवादी - आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील कुमार ने विद्वान सॉलिसिटर जनरल की दलीलों का समर्थन किया।

श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील जिन्होंने लालू प्रसाद यादव की ओर से बहस की ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि एकमात्र परीक्षण यह है कि कार्यवाही चल रही है या नहीं विशेष रूप से झारखंड राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से संबंधित स्थानांतरित करने की मांग की गई है और तथ्यों पर यह नहीं कहा जा सकता है, किसी भी कल्पना से, कि मामले विशेष रूप से उस क्षेत्र से संबंधित हैं। इसमें वर्णित कृत्यों के मद्देनजर आर.सी. में दाखिल की गई आरोप-पत्र 20ए, आर.सी._30 ए और आर.सी. 64ए. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 178 से 180 में प्रतिपादित सिद्धांत ऐसा कर सकते हैं लागू किया जाना चाहिए और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित आपराधिक कदाचार को विशेष रूप से झारखंड राज्य से संबंधित नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत स्थिति के अनुसार भी पटना के साथ-साथ झारखंड क्षेत्र में स्थित लोक सेवकों द्वारा किए गए कृत्यों के परिणामस्वरूप अपराध हुआ है और परिणामस्वरूप अधिनियम धारा 89 में परिकल्पित विशिष्टता की परीक्षा हुई है। इन अपीलों में शामिल मामलों की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र से पटना की न्यायालयों को मुक्त नहीं कर सकता है।

डॉ.जगन्नाथ मिश्रा की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी.एस.मिश्रा ने बताया कि तथ्य यह है कि सीबीआई ने पटना की न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था, यह इस स्थिति के कारण था कि पटना की न्यायालयों का क्षेत्राधिकार था। मामले की सुनवाई के लिए. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर संहिता की धारा 79 और 180 के मद्देनजर विचार किया जाना चाहिए और अधिनियम की धारा 89 में "विशेष रूप से" शब्द का "अन्य सभी को छोड़कर" के अलावा कोई अर्थ नहीं हो सकता है। अन्य कुछ उत्तरदाताओं की ओर से बहस कर रहे विद्वान वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा ने उन्हीं तर्कों को अपनाया जो ऊपर उल्लिखित दो वरिष्ठ वकीलों द्वारा सामने रखे गए हैं।

अधिनियम की धारा 89 इस बात से संबंधित है कि झारखंड राज्य के "विशेष रूप से क्षेत्र से संबंधित" प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में नियत दिन यानी 15.11.2000 को क्या होना चाहिए था। ऐसी प्रत्येक कार्यवाही "झारखंड राज्य के संबंधित न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी को हस्तांतरित कर दी जाएगी"। यहां "विशेष रूप से झारखंड राज्य के क्षेत्र से संबंधित" हैं, शब्द निर्णायक शब्द हैं। इस सन्दर्भ में "विशेष रूप से" शब्द का क्या अर्थ है? यह अब निर्धारित करना होगा.

ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, "विशेष रूप से" शब्द को कई बारीकियों या अर्थों के अर्थों में दिखाया

गया है जैसे "केवल या पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से सभी या बड़े हिस्से के लिए"। इसका अर्थ "अन्य सभी को छोड़कर" भी है। विद्वान वकील जिन्होंने इस सिद्धांत के पक्ष में विचार प्रस्तुत किया कि मामले झारखंड राज्य में स्थानांतरित कर दिए गए थे, उन्होंने कहा कि उपरोक्त विभिन्न अर्थों में से इस शब्द को केवल "पर्याप्त रूप से सभी या बड़े हिस्से के लिए" के रूप में समझा जाना चाहिए क्योंकि यह इसके लिए सबसे उपयुक्त प्रसंग है। दूसरे पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उक्त शब्द का अर्थ "अन्य सभी को छोड़कर" के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी के कोशकार ने इस वाक्यांश का उल्लेख किया है "विशेष रूप से प्रयुक्त" और साल्वेशन आर्मी बनाम होहेन (मो., 354, मो.107, 188 एसडब्ल्यू 2डी 826) से उद्धृत इस प्रकार है:

"प्रावधान में वाक्यांश विशेष रूप से कराधान संपत्तियों से छूट देता है धार्मिक पूजा के लिए, स्कूलों के लिए या विशुद्ध रूप से धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें प्राथमिक और अंतर्निहित का संदर्भ है, न कि मात्र माध्यमिक का और आकस्मिक उपयोग का।"

विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने हमारा ध्यान अनोका काउंटी बनाम सेंट पॉल शहर, [1999] अमेरिकी कानून रिपोर्ट 1137 में मिनेसोटा सुप्रीम कोर्ट के डेवेनी, जे. द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया। उस मामले में विद्वान न्यायाधीश अनुच्छेद 9, मिनेसोटा संविधान की धारापर विचार कर रहे थे। "किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक संपत्ति" को कराधान से छूट दी गई थी। यह तर्क दिया गया था कि चूंकि शहर आंशिक रूप से था, कम से कम एक निजी व्यवसाय में संलग्न था, जिस भूमि पर पानी का काम किया गया था उसका उपयोग विशेष रूप से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था और इसलिए पूरे जल कार्यों पर कर लगाया जाना चाहिए। उक्त तर्क को निम्नलिखित शब्दों द्वारा खारिज कर दिया गया था:

"हम सहमत नहीं हैं। यहाँ 'विशेष रूप से' शब्द का प्रयोग किया गया है का अर्थ 'काफी हद तक' या 'बड़े हिस्से के लिए है'। इस शब्द एक व्यावहारिक अर्थ होना चाहिए।"

हम बता सकते हैं कि उपरोक्त अवलोकन का उपयोग कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम के संपादकों द्वारा लाभप्रद रूप से किया गया है (खंड 33 के पृष्ठ एलएफ3 के अनुसार)। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन बनाम मैडिसन शहर के मूल्यांकनकर्ता, (406 एनवाईएस 583) में "शब्द और वाक्यांश" से एक उद्धरण इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"शब्द 'विशेष रूप से', जैसा कि वास्तविक संपत्ति कर कानून के प्रावधान में उपयोग किया जाता है। किसी निगम के स्वामित्व वाली वास्तविक संपत्ति को कराधान से

छूट देना विशेष रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आयोजित या संचालित किया जाता है और विशेष रूप से ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है 'प्राथमिक रूप से'।"

क्लैमथ सिंचाई जिले बनाम रोजगार प्रभाग, (534 पृ. 2डी 190) से एक और उद्धरण को भी इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत "अनन्य" शब्द कृषि श्रमिकों को बेरोजगारी मुआवजा करों के भुगतान से छूट को परिभाषित करता है, जिसमें खाइयों, नहरों, जलाशयों या जलमार्गों के संचालन या रखरखाव के संबंध में की गई सभी सेवाएं शामिल हैं जिनका स्वामित्व नहीं है या लाभ के लिए संचालित, विशेष रूप से खेती के प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति और भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। एक सिंचाई जिले को कर भुगतान के बोझ से राहत देने के लिए संचालित होता है, यदि उसका कोई भी पानी लाभ के लिए नहीं बेचा जाता है और यदि संगठन प्राथमिक रूप से या 'मुख्य रूप से' या 'में समर्पित है वितरित करने के लिए 'बड़ा हिस्सा' कृषि उद्देश्यों के लिए पानी, और यदि गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए पानी डाला जाता है तो वह 'पर्याप्त' नहीं है।"

हमने यह निर्धारित करने के लिए कि अधिनियम की धारा 89 में आने वाले उक्त शब्द की व्याख्या के लिए उनमें से किसे चुना जाना है, उपरोक्त विभिन्न अर्थों की ओर इशारा किया है। नोस्किटुर ए सोसिसिस (किसी शब्द का अर्थ उसके साथ आने वाले या संबद्ध शब्दों से पता होना चाहिए) का सिद्धांत किसी वैधानिक प्रावधान में शब्दों के महत्व को समझने में बहुत प्रासंगिक है। इस न्यायालय द्वारा बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पु [1978] 2 एससीसी 213, रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम सीसीई, (1990) जैसे कई मामलों में उक्त सिद्धांत का लाभ उठाया गया है। 3 एससीसी 447, ओसवाल एगो मिल्स लिमिटेड बनाम सीसीई [1993] सप्लिमेंट 3 एससीसी 716, के. भागीरथी जी. शेनॉय और अन्य बनाम के.पी. बल्लाकुरया और एएम [1999] 4 एससीसी 135, लोकमत न्यूजपेपर्स (पी) लिमिटेड बनाम शंकरप्रसाद, [1999] 6 एससीसी 275।

यदि ऐसा है, तो हमें आस-पास के संदर्भ से "विशेष रूप से क्षेत्र से संबंधित कार्यवाही" शब्दों के निहितार्थ का आकलन करना होगा। अधिनियम की धारा 89 कहती है कि नियत दिन से पहले "किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय के अलावा), न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी" के समक्ष लंबित कार्यवाही को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। झारखंड राज्य का "संबंधित न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी"। अनुभाग में "झारखंड राज्य में संबंधित न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी" शब्दों को इस प्रकार परिभाषित करके [एक बहुत उपयोगी सूचकांक] प्रदान किया गया है:

"वह न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी जिसमें या जिसके समक्ष कार्यवाही रखी गई होती यदि इसे नियत दिन के बाद शुरू किया गया होता।"

इन शब्दों पर गौर करें "यदि इसे नियत दिन के बाद स्थापित किया गया होता तो इसे समाप्त कर दिया गया होता"। इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि कार्यवाही कहाँ से संबंधित है, इन अपीलों में शामिल 36 मामलों को रखा गया होता, यदि उन्हें नियत दिन के बाद स्थापित किया जाता , तो हमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि "विशेष रूप से" शब्द का अर्थ "काफी हद तक या बड़े हिस्से के लिए या मुख्य रूप से" समझा जाना चाहिए।

हम अधिनियम की धारा 89 के मुख्य उद्देश्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह नहीं भूलना चाहिए कि आपराधिक मामलों का स्थानांतरण ही एकमात्र विषय नहीं है। यह प्रावधान विभाजन के बाद सभी कार्यवाहियों से संबंधित फाइलों या अभिलेखों को आवंटित करने का प्रयास करता है, यदि उन्हें नियत दिन के बाद स्थापित किया जाना था। कोई भी व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो उस उद्देश्य को प्राप्त करे, न कि वह जो संबंधित राज्यों के अधिकारियों के लिए भ्रम या परेशानी या यहां तक कि घबराहट पैदा कर सकती है। दूसरे शब्दों में, व्याख्या व्यावहारिकता के साथ की जानी चाहिए, न कि पांडित्यपूर्ण या संकीर्ण तरीके से। आपराधिक मामलों के प्रयोजन के लिए, हमें स्थानांतरित किए जाने वाले मामले की विषय-वस्तु को ध्यान में रखना चाहिए। इस पर विचार करते समय, हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सभी 36 मामले मुख्य रूप से पीसी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए हैं और इसलिए वे सभी विशेष न्यायाधीशों की न्यायालयों के समक्ष विचारणीय हैं। इसलिए, वर्तमान प्रश्न को पीसी अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है।

इन सभी मामलों में आरोप पत्र विशेष न्यायालय पटना में न्यायाधीश के समक्ष दाखिल किये गये थे पटना में न्यायाधीश जब 15.11.2000 से पहले बिहार राज्य अविभाजित था । अधिसूचना दिनांक 5.6.1996 द्वारा उस न्यायालय को पीसी अधिनियम के तहत आने वाले सभी मामलों की सुनवाई के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था। इसमें तब जोड़ा गया जब पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने (सही या गलत) जिला और सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिया कि पशुपालन घोटाले से संबंधित सभी मामले (बिहार चारा घोटाले के मामलों के समान) उस न्यायालय में दायर किए जाएं, तब सीबीआई के पास कोई विकल्प नहीं था। मामला उन सभी मामलों को पटना की न्यायालय के समक्ष दायर करने के अलावा। इसमें कोई विवाद नहीं है कि 15.11.2000 को पटना की न्यायालय को झारखंड राज्य के भीतर आने वाले क्षेत्रों पर उसके अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दिया गया था।

पीसी अधिनियम की धारा 4 उस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। धारा 4 की पहली उपधारा यह घोषणा करती है कि संहिता या किसी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद, पीसी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई एवं कार्यवाही पीसी की धारा 3(1) के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश द्वारा "केवल" ही की जा सकती है। धारा की उपधारा (2) 4 में महत्वपूर्ण प्रावधान है और इसे नीचे दिया गया है:

"धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपराध का विचारण उस क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा जिसके अन्तर्गत यह किया गया था, या, जैसा भी मामला हो, मामले के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश द्वारा, या, जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायाधीश होते हैं, उनमें से एक ऐसा होता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

इस प्रकार, एकमात्र न्यायालय जिसके पास इसके तहत अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है पीसी एक्ट उन क्षेत्रों के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश की न्यायालय है जिनके अन्तर्गत ऐसे अपराध किए गए थे। ऐसे किसी अपराध का विचारण जब किया जा रहा हो तो उपधारा (3) उसी विशेष न्यायाधीश को किसी अन्य अपराध की सुनवाई करने में सक्षम बनाता है जो उसी मुकदमे में उस आरोपी के खिलाफ लगाया जा सकता है। मामले की धुरी यह है कि उस क्षेत्र का निर्धारण करना जिसके क्षेत्र में अपराध किया गया था।

उस उद्देश्य के लिए पीसी अधिनियम की धारा 3(1) को देखना उपयोगी है। यह यह सरकार को दो श्रेणियों के अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार देता है। पहला "इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई भी अपराध और दूसरा, पहली श्रेणी में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी को करने की कोई साजिश या कोई प्रयास या किसी भी अपराध के लिए उकसाना"। इसलिए जब किसी न्यायालय के पास मुकदमा चलाने का क्षेत्राधिकार होता है पीसी अधिनियम के तहत उस स्थान के आधार पर दंडनीय अपराध जहां ऐसा अपराध किया गया था, संबद्ध अपराध जैसे कि साजिश, प्रयास या उस अपराध को करने के लिए उकसाना केवल मुख्य अपराध से जुड़ा होना चाहिए। मुख्य अपराध जब किया जाता है और मुकदमा चलाने की आवश्यकता है, यह समझ से परे है कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि इस तरह के मुख्य अपराध की षड़यंत्र या प्रयास या दुष्प्रेरण कहां किया गया था। यह केवल तब होता है जब मुख्य अपराध नहीं किया गया था, बल्कि केवल साजिश उस अपराध को अकेले करना या उसका प्रयास करना या उकसाना किया गया था, तो यह प्रश्न उठेगा कि क्या विशेष न्यायाधीश की न्यायालय, जिसके क्षेत्र में ऐसी षड़यंत्र आदि की गई थी, मामले की सुनवाई कर सकती है। हमारे उद्देश्य के लिए उस पहलू पर विचार करना अनावश्यक है क्योंकि आरोप इसी धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि मुख्य अपराध किया गया था।

इन सभी 36 मामलों में लगे आरोपों में मुख्य अपराध क्या है?

यह निर्विवाद है कि मुख्य अपराध पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(सी) और धारा 13(1)(डी) के तहत है। उनमें से प्रथम का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

" एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार का अपराध करना कहा जाता है,

(ग) यदि वह बेईमानी से या धोखाधड़ी से दुरुपयोग करता है या अन्यथा

उसे सौंपी गई या उसके अधीन किसी भी संपत्ति को अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है

एक लोक सेवक के रूप में उसका नियंत्रण या किसी अन्य व्यक्ति को करने की अनुमति देता है।"

अगले अपराध का वर्णन इस प्रकार किया गया है। यह:

" एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार का अपराध करना कहा जाता है, -

(डी) यदि वह,-

(i) भ्रष्ट या अवैध तरीकों से, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

(ii) एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

(iii) एक लोक सेवक के रूप में पद पर रहते हुए, किसी भी व्यक्ति के लिए बिना किसी सार्वजनिक हित के मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है।"

हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि पहले इस अधिनियम के केंद्र की परिकल्पना की गई थी उन दो अपराधों में से एक है "बेईमानी से या धोखाधड़ी से गलत तरीके से दुरुपयोग करना"। इसी प्रकार दूसरे खंड में परिकल्पित अधिनियम का आधार भ्रष्ट या अवैध साधन द्वारा अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ "प्राप्त करना" है।

उपरोक्त कार्य वर्तमान मामलों में तब पूरे किये गये जब पैसा सार्वजनिक खजाने से बाहर चला गया हो और इसमें शामिल किसी एक व्यक्ति के हाथों में पहुंच गया हो। इसलिए, जहां तक धारा 13(1)(सी) और धारा 13(1)(डी) के तहत अपराधों का संबंध है, वह स्थान जहां अपराध किए गए थे आसानी से उस स्थान के रूप में पहचाना जा सकता है जहां संबंधित खजाना स्थित था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि इन सभी मामलों में राजकोष झारखंड राज्य के क्षेत्र के भीतर स्थित थे।

इस प्रकार, जब यह निश्चित हो जाता है कि पीसी अधिनियम की धारा 13 के तहत अपराध वास्तव में कहां किया गया था, तो अन्य क्षेत्रों पर विचार करना एक अनावश्यक अभ्यास है जिसमें कुछ संबद्ध गतिविधियां, जैसे षड़यंत्र या तैयारी, या यहां तक कि प्रारंभिक या आकस्मिक कृत्य भी किए गए थे, जिसमें परिणाम भी शामिल हैं।

इस संदर्भ में संहिता की धारा 181 का उल्लेख करना उपयोगी है जो अध्याय 11 के अंतर्गत आता है, जिसमें पूछताछ और परीक्षाओं में आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बारे में प्रावधान शामिल हैं। धारा 181 "कुछ अपराधों के मामले में सुनवाई के स्थान" से संबंधित है। इसकी उपधारा (4) न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, यदि किया गया अपराध या तो आपराधिक दुरुपयोग है या आपराधिक विश्वास का उल्लंघन है। उक्त अपराध की सुनवाई के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाली

उप-धारा द्वारा कम से कम चार अलग-अलग न्यायालयों की परिकल्पना की गई है और इनमें से कोई एक जिसे चुना जा सकता है. वे इस प्रकार हैं: (1) वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अपराध किया गया था; (2) वह न्यायालय जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में संपत्ति का कोई भी हिस्सा जो अपराध का विषय है, प्राप्त किया गया था; (3) वह न्यायालय जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में संपत्ति का कोई भी हिस्सा जो अपराध का विषय है, बरकरार रखा गया था; और (4) वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपत्ति का कोई भी हिस्सा जो अपराध का विषय है, अभियुक्त द्वारा वापस लौटाया जाना या उसका हिसाब देना आवश्यक था।

अब, संहिता की धारा 181(4) और पीसी अधिनियम की धारा 4(2) के बीच अंतर पर गौर करें। पूर्व प्रावधान में जब हेराफेरी से जुड़े किसी मामले की सुनवाई के लिए अधिकार क्षेत्र रखने वाली कम से कम चार न्यायालयों की परिकल्पना की गई थी, तो पीसी अधिनियम के बाद के प्रावधान ने इसे एक न्यायालय यानी विशेष न्यायालय तक सीमित कर दिया है। उस क्षेत्र के लिए न्यायाधीश जिसके अन्तर्गत अपराध किया गया था। ऐसा कोई अपराध करना या करने का प्रयास करना या उसके लिए उकसाना, वह न्यायालय जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में मुख्य अपराध था अकेले प्रतिबद्ध क्षेत्राधिकार है.

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पीसी अधिनियम की धारा 4(2) क्षेत्राधिकार के संबंध में संहिता के प्रावधानों को खत्म नहीं करती है, क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 4 में सम्मिलित चार उपधाराओं में से केवल प्रथम एवं अंतिम उपधारा ही टैग की गयी है, अप्रचलित शब्दों के साथ "आपराधिक प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी"। उनके निवेदन में यह तथ्य कि उप-धारा (2) को गैर-अस्पष्ट शब्दों से मुक्त किया गया है, यह दर्शाता है कि संहिता के प्रावधानों को उस उप-धारा के साथ भी पढ़ा जा सकता है। उस संदर्भ में विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारा ध्यान संहिता की धारा 178 से 180 की ओर आकर्षित किया, जिसमें दिखाया गया है कि अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रों पर अधिकार रखने वाली विभिन्न न्यायालयों के पास अपराधों की जांच करने या मुकदमा चलाने के लिए समवर्ती क्षेत्राधिकार है और इसलिए उनमें से किसी एक में मुकदमा चलाने की अनुमति है।

पीसी अधिनियम की धारा 4(2) से जुड़े एक गैर-अप्रत्याशित खंड की अनुपस्थिति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि उप-धारा संहिता के प्रावधानों के अधीन है। संहिता की धारा 4(2) (पीसी अधिनियम नहीं) को पढ़ने से यह पता चलता है निश्चित संकेत है कि कानूनी स्थिति दूसरी तरह से है। इस संहिता की धारा 4, भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत अपराधों के मुकदमे के संबंध में है। इसकी उपधारा (1) केवल भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराधों से संबंधित है। उप-धारा (2) "किसी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों" को अस्वीकार करती है। इस स्तर पर

उक्त उपधारा को पढ़ना उपयोगी है:

"किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच की जाएगी, कोशिश की जाएगी, और अन्यथा समान प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा, लेकिन जांच, पूछताछ, कोशिश या प्रयास करने के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी भी समय के लिए लागू किसी भी अधिनियम के अधीन होगा अन्यथा ऐसे अपराधों से निपटना होगा।"

इस प्रकार, यदि पीसी अधिनियम ने उस अधिनियम के तहत अपराध के परीक्षण के लिए कोई स्थान निर्धारित किया है तो परीक्षण के स्थान के संबंध में संहिता के प्रावधान उस सीमा तक विस्थापित हो जाएंगे। इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अपराध पीसी अधिनियम की धारा 13.(1)(सी) या धारा 13(1)(डी) के तहत होता है तो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में एकमात्र निर्धारक कारक वह स्थान होता है जहां अपराध कारित होता है।

हमारे सामने उद्धृत विभिन्न निर्णयों में से, केरल उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किया गया है और उसमें की गई टिप्पणियों पर प्रकाश डाला गया है। बनवारीलाल झुनझुनवाला और अन्य बनाम भारत संघ, एआईआर (1959) केरल 311 पी.टी. रमन नायर, जे. (तब विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) को अपराध के संबंध में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के सवाल पर विचार करना था। 1947 के पीसी अधिनियम की धारा 5(2) कुछ अन्य दंड संहिता अपराधों के साथ मेल खाती है। उस मामले में तथ्य यह थे कि दो आरोपियों ने केंद्रीय रेलवे प्रशासन के लिए लकड़ी की आपूर्ति के लिए नई दिल्ली में अनुबंध किया लेकिन लकड़ी की खेप बम्बई, हैदराबाद और झाँसी में थी। लकड़ी की आपूर्ति के लिए, बिल पारित किए गए और चेक के अनुसार भुगतान नई दिल्ली में किया गया, जिसे बॉम्बे में भुनाया गया लेकिन केरल राज्य के भीतर निम्न गुणवत्ता वाली लकड़ी की आपूर्ति की गई। ऐसी लकड़ी की अच्छी गुणवत्ता का प्रमाणपत्र केरल राज्य में स्थित विभिन्न स्थानों पर रेलवे बोर्ड, बॉम्बे के निरीक्षण अधिकारी थॉमसन द्वारा जारी किया गया था। उक्त अधिकारी पर अन्य आरोपियों के साथ उपरोक्त अपराधों के लिए केरल में एक विशेष न्यायाधीश की न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया गया था। मुख्य आरोपी - थॉमसन - ने केरल स्थित उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि "पीसी अधिनियम की धारा 5(2) के तहत पहला अपराध, जिसे थॉमसन द्वारा कथित तौर पर किया गया था, को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह केरल राज्य के भीतर संयुक्त था जहां उसने घटिया जंगल की लकड़ी को लकड़ी के रूप में अनुबंध की गुणवत्ता के बारे में और उसके लिए गलत प्रमाणपत्र जारी किया था।"

विद्वान न्यायाधीश के समक्ष यह तर्क दिया गया कि केरल राज्य के बाहर षड़यंत्र हुई थी

और इसलिए संहिता की धारा 180 लागू होगी। उक्त विवाद को खारिज करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार कहा:

"धारा 180, दंड प्रक्रिया संहिता का अनुप्रयोग और भी अधिक निश्चित है। उकसाने जैसी साजिश कोई ऐसा कार्य नहीं है जो स्वाभाविक रूप से अपराध हो। यह दूसरे कार्य से इसका संबंध है जो इसका उद्देश्य है जो इसे अपराध बनाता है। इस विशेष मामले को लेते हुए, यह साजिश के संबंध में विचार किए गए कार्य के कारण है, अर्थात्, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत एक अपराध का कमीशन, जो साजिश को अपराध बनाता है; और ऐसा है कि क्या वह अन्य कार्य करता है किया गया है या नहीं। एक कृत्य का दूसरे कृत्य से संबंध होने के लिए यह पर्याप्त है कि वह दूसरा कृत्य चिंतन में हो, यह आवश्यक नहीं कि वह वास्तव में किया ही जाए।"

इस प्रकार दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तावित उक्त निर्णय पर भरोसा किया गया है यह इसका समर्थन करेगा कि अधिकार क्षेत्र का स्थान उस स्थान के संदर्भ में निर्धारक होगा जहां मुख्य अपराध किया गया था। यह तथ्य कि अन्य संबद्ध कृत्य अलग-अलग स्थानों पर किए गए थे, मुकदमे के स्थान को ऐसे अन्य स्थानों में बदलने के लिए शायद ही पर्याप्त होगा।

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने धनेश्वर नारायण सक्सेना बनाम दिल्ली प्रशासन, [1962] 3 एससीआर 259, एम. नारायणन नांबियार बनाम केरा राज्य, (1963) • पूरक 2 एससीआर 724, गुजरात राज्य बनाम मानशंकर प्रभाशंकर द्विवेदी[972] 2 एससीसी 392, मेजर एस.के. काले बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1977] 2 एससीसी 394 और भारत संघ बनाम एमएलआई जे.सी. लाला आदि, (1973] 2 एससीसी 72. के निर्णयों का हवाला दिया। इन सभी निर्णयों में कारित अपराध करने के लिए आवश्यक विभिन्न सामग्रियों पर विचार केन्द्रित किया गया। लेकिन इनमें से किसी भी मामले में मौजूदा स्थिति से संबंधित किसी प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था। के. भास्करन बनाम शंकरन वैद्यन बालन और अन्ना[999] 7 सेकंड 510 (विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उद्धृत) में इस सवाल पर विचार किया गया था कि क्या किसी विशेष न्यायालय के पास धारा 138 के तहत अपराध की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। इन निर्णयों से इन अपीलों में शामिल महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर तक पहुँचने में भी कोई मदद नहीं मिलती

श्री पी.एस. मिश्रा विद्वान वरिष्ठ वकील ने पुरुषोत्तमदास डालमिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1962] 2 एससीआर 101 और एल.एन. । मुखर्जी बनाम मद्रास राज्य[1962] 2 एससीआर 116 मामले के निर्णयों का हवाला दिया। पूर्व में यह माना गया था कि जिस न्यायालय के पास षड्यंत्र के अपराध की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, वह साजिश के तहत किए गए प्रत्यक्ष कृत्यों से

भी निपट सकती है, बाद वाला फैसला विपरीत स्थिति से चिंतित है। ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में यह महत्वहीन है कि क्या उन मामलों की परिस्थितियों में ऐसी अन्य न्यायालय का भी क्षेत्राधिकार होगा।

श्री पी.एस. मिश्रा विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारा ध्यान बनवारी लाल झुनझुनवाला और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1963] पूरक 2 एससीआर 338 मामले में इस न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया। हम बता सकते हैं कि यह वही मामला है जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों में क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर निर्णय लिया था। उक्त मामले की जब एक शाखा इस न्यायालय में पहुंची तो यहां सवाल इस बात पर केंद्रित था कि क्या धोखाधड़ी के उद्देश्य से बनाए गए अलग-अलग बिलों को अलग-अलग अपराध से संबंधित माना जाएगा, जिसमें अलग-अलग आरोप तय किए जाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान मामलों में शामिल प्रश्न के लिए हमें उक्त निर्णय से कोई सहायता नहीं मिलती है।

अब हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। हमारे विचार में इन अपीलों में शामिल सभी 36 मामले अधिनियम की धारा 89 के संचालन द्वारा नियत दिन (यानी 15.11.2000) को झारखंड राज्य के क्षेत्रों में स्थित संबंधित न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिए गए। इसलिए, हम पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को निर्देश देते हैं कि वे इन सभी 36 मामलों के रिकॉर्ड को तुरंत झारखंड राज्य की संबंधित न्यायालयों में भेजने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें। हम झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को भी निर्देश देते हैं कि ऐसे अभिलेखों तक उचित न्यायालयों में पहुंचाने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करें।

भ्रम और अभ्यास की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि 36 मामलों में से किसी में पहले से दर्ज किए गए साक्ष्य को अधिकार क्षेत्र वाले उचित न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, विशेष न्यायाधीश को पहले से जांचे गए गवाहों को दोबारा बुलाने की आवश्यकता नहीं है जो पहले ही रिकॉर्ड में आ चुका है उसे दोहराया ना जा सके।

आक्षेपित निर्णयों को रद्द किया जाता है और अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अपील निस्तारित.

हिन्दी अनुवादित किया गया

अमित राज

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-
विशेष उत्पाद न्यायाधीश,द्वितीय
कटिहार।